

(b) if so, the facts and details in this regard;

(c) whether the use of cow and beef fat is permissible in manufacturing toffees and chewinggums; and

(d) if not, what action Government propose to take against the company?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) The Government has not granted any approval to M/s. Pepsi Foods Limited or to M/s. Pepsico India Holdings for manufacture of chewing-gum. M/s. Pepsi Foods Limited have also stated that neither they nor M/s. Pepsico India Holdings or any of its subsidiaries manufactures or markets chewinggum.

(c) No, Sir.

(d) In view of (c) above, no action is called for.

Pending applications for Approval for the Production of Naphtha NGL

*132 SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether the export of Naphtha/NGL is made only after meeting the demand of indigenous industry;

(b) if so, the number of files/cases pertaining to the allocation/administrative final approval of NGL/Naphtha are pending in MoS office since the past one month; and

(c) the reasons for not granting final approval to the cases pending since the past more than one month?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A number of applications for allocation of Naphtha/NGL are

received from various firms/companies. As NGL/Naphtha are highly inflammable products and can be used for adulteration of petrol/diesel, the applications are minutely scrutinised and carefully processed in consultation with the Oil Companies, Oil Coordination Committee, various sponsoring Ministries/Departments like Ministry of Power, Department of Chemicals and Petrochemicals, Department of Fertilizers, Ministry of Steel and expert opinion. The applicants are required also to furnish certificates/clearances from various authorities like the State Pollution Control Board, the Chief Controller of Explosives, Directorate of Industries of State, etc. As allocation is based on recommendations/clearances of other Ministries/authorities, expert opinion and logistic feasibility, the process is inherently time-consuming and it takes time to take final decision. All efforts are made to expedite decision.

दूरसंचार निगम द्वारा विदेशी बाज़ार से संसाधनों का जुटाया जाना

133 श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार निगम ने अपनी आधुनिकीकरण और विकास योजनाओं के लिए विदेशी बाज़ार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का निर्णय लिया है,

(ख) क्या दूरसंचार निगम विदेशी बाज़ार में यूरो वाण्ड जारी करने का विचार रखता है, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा,

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):
(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मामले में नीचे उत्तर (ग) (i) के अनुसार

(ग) (i) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा विश्व बाज़ार में 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य बंधपत्र जारी करने का प्रस्ताव, हाल ही में

वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

(ii) विदेश संचार निगम लिमिटेड, आधुनिकीकरण एवं विकास परियोजनाओं के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के वाणिज्यिक ऋण के बारे में बातचीत कर रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन न किया जाना

134. श्री ईश दत्त यादव: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि होने का मुख्य कारण सरकार की प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नीतियों का कार्यान्वयन न किया जाना है,

(ख) यदि हां, तो इन नीतियों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने की दृष्टि से सरकार इन नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस उपाय कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) प्रदूषण में वृद्धि के मुख्य कारण मुख्यतया उद्योगों से तरल बहिस्त्रावों तथा गैसीय उत्सर्जनों के निपटान तथा नगरीय मलजल तथा घरेलू अपशिष्टों के अंधाधुंध निपटान के कारण होता है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से योगदान करते हैं। सरकार ने देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए हैं। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है:—

1. उद्योगों को स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए बड़ावा दिया जाता है ताकि अपशिष्टों का सृजन कम हो।

2. सल्फर डाईआक्साइड उत्सर्जनों को रोकने के लिए कतिपय संवेदनशील क्षेत्रों और चार महानगरों को अल्प-सल्फर डीजल मुहैया कराया जायेगा।

3. केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर कम करने

के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। देश में ऐसे 24 क्षेत्रों की पहचान की गई है;

4. प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख श्रेणियों के लिए उत्सर्जन और बहिस्त्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

5. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ऐसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करें तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

6. वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत पेट्रोल और डीजल चालित वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अन्तर्गत यानीय उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानक अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।

7. मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

8. दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार महानगरों में कैटेलिटिक कन्वर्टर युक्त कारों के लिए 1.4.1995 से सीमा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

9. उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं।

10. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

11. प्रदूषण नियंत्रण / निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है।

12. लघु औद्योगिक समूहों में साझे बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

13. गंगा कार्य योजना चरण-1 पूरी होने को है तथा सरकार ने गंगा कार्य योजना चरण-2 के अन्तर्गत यमुना और गोमती कार्य योजनाएं मंजूर की हैं जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय नदी कार्य योजना को भी अनुमोदित कर दिया है जिसके तहत प्रदूषित नदी के उन अभिनिर्धारित